

मुकदमों का विवरण

सोलरिस चेम टेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम.

सहायक एकजीक्यूटिव इंजीनियर कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और ड्राइनेज बोर्ड और ए. एन. आर. (2023 की सिविल अपील संख्या 6609)

10 अक्टूबर, 2023

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड, सीजेआई, जे. बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या उच्च न्यायालय को पक्षकारों के बीच समझौतों के खंड 11 के बल पर रिट याचिका और रिट अपील को खारिज करने में न्यायसंगत ठहराया गया था; और क्या पक्षकारों के बीच एक वैध मध्यस्थता समझौता था, जो खंड 11 के तहत मुख्य अभियंता को भेजे जाने को न्यायसंगत ठहराता है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996।7(1), 2(ख)** वैध मध्यस्थता समझौता-तथ्यों पर, समझौतों के खंड **11** के संदर्भ में, पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का समाधान पारस्परिक चर्चा और प्रक्रिया की विफलता पर, मामले को मुख्य अभियंता के पास भेजकर किया जाएगा, जिसका निर्णय शून्य और बाध्यकारी होगा-पानी की आपूर्ति के लिए शुल्क के बकाया की मांग करने वाले नोटिस को चुनौती देने वाली रिट याचिका-एकल न्यायाधीश ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को समझौते के संदर्भ में संविदात्मक उपचार के लिए भेज दिया-खंड पीठ ने इसे बरकरार रखा-शुद्धता:

आयोजित किया गया: खंड 11 एक मध्यस्थता समझौते का गठन नहीं करता है-समझौते का खंड 11.2 मुख्य अभियंता को एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण के रूप में गठित नहीं करता है-समझौते यह नहीं मानते हैं कि मुख्य अभियंता पक्षों के बीच विवादों पर निर्णय लेगा और न ही इस आशय का कोई प्रावधान है कि मुख्य अभियंता साक्ष्य देने या पक्षों को उनके सामने अपने-अपने मामलों को प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद विवाद का समाधान करेगा-मुख्य अभियंता वाले मंच में मध्यस्थता मंच का अभाव है-मुख्य अभियंता बोर्ड का एक कर्मचारी है-हालांकि 464

463

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

एकल न्यायाधीश का विचार था कि समझौते के खंड 4 ने बोर्ड को अपनी दरों को संशोधित करने का अधिकार दिया, फिर भी, शक्ति और उसके प्रयोग के तरीके से आगे विचार किए बिना, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को मुख्य अभियंता के समक्ष खंड 11 के तहत उपचार के लिए हटा दिया-

उच्च न्यायालय को खंड 11 के बल पर मुख्य अभियंता के पास पक्षों को नहीं भेजना चाहिए था-यह उचित होता अगर उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कार्यवाही में अपीलकर्ता द्वारा संबोधित चुनौती को पूरी तरह से निर्धारित किया होता-खंड पीठ ने इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए विशेष रूप से खंड 11 के प्रावधानों पर भरोसा किया कि पक्षों के बीच विवाद खंड में निहित विवादों के निपटारे के प्रावधान के दायरे में आता है।[पारस 16-18,22-26]

मध्यस्थता-वैध मध्यस्थता समझौता-संतुष्ट करने के लिए शर्तें-उल्लिखित।[पैरा **19**]

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

जगदीश चंदर बनाम रमेश चंदर (2007) 5 एससीसी 719:[2007] 5 एस. सी. आर. 720; जयपुर जिला दुध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बनाम अजय सेल्स एंड सप्लायर 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 730; वॉइस्टाल्पाइन शियेनन जी. एम. बी. एच. बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2017) 4 एस. सी. सी. 665:[2017] 1 एस. सी. आर. 798; एलोरा पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम.एम. पी. राज्य (2022) 3 एस. सी. सी. 1-निर्दिष्ट।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील संख्या 6609।2018 के डब्ल्यू. ए. सं. 100073 में धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ के दिनांक 18.06.2018 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

दलीप कुमार मल्होत्रा, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

दर्पण के. एम., सुश्री अमृता शर्मा, सुश्री राशि बंसल, रजत जोनाथन शॉ, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सोलारिस चेम टेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम असिस्टेंट

465

एकजीक्यूटिव इंजीनियर कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और ड्राइंग बोर्ड 466

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

आदेश

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील धारवाड़ पीठ में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के 18 जून 2018 के एक फैसले से उत्पन्न होती है। डिवीजन बेंच ने एक रिट अपील को खारिज कर दिया है और इस तरह अपीलार्थी के नेतृत्व में रिट याचिका को खारिज करने वाले एकल न्यायाधीश के 27 फरवरी 2018 के आदेश की शुद्धता को खारिज कर दिया है।

3. अपीलार्थी ने 1975 में मैसूर के उत्तरी कनारा जिले के बिनागा गाँव में कास्टिक सोडा के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित किया। 5 जुलाई 1971 को मैसूर सरकार और अपीलार्थी के बीच कारखाने के संचालन के लिए रियायती दरों पर पानी की निरंतर आपूर्ति के लिए एक समझौता किया गया था। यह समझौता उत्पादन शुरू होने से 20 साल की अवधि के लिए वैध था। 3 अप्रैल 1987 को राज्य सरकार ने कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और जल निकासी बोर्ड अधिनियम, 1973 के अनुसार कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और जल निकासी बोर्ड 1 का गठन किया। बोर्ड अपीलार्थी को औद्योगिक उपयोग के साथ-साथ गैर-घरेलू उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति कर रहा था।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि मूल समझौतों को औद्योगिक और गैर-घरेलू उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति से संबंधित बाद के समझौतों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। वर्तमान विवाद से संबंधित अंतिम समझौते 11 नवंबर 2011 को किए गए थे, जिसमें पानी की आपूर्ति के लिए क्रमशः गैर-घरेलू उपयोग और औद्योगिक उपयोग के लिए शुल्क लिया गया था। ये समझौते 27 अक्टूबर 2011 से 26 अक्टूबर 2014 तक प्रभावी रहे। समझौतों के संदर्भ में, औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति के लिए शुल्क 18.40 प्रति किलोलीटर और गैर-घरेलू उपयोग के लिए 9.20 रुपये प्रति किलोलीटर निर्धारित किया गया था। 6 जून 2014 और 16 सितंबर 2014 के बीच, 11 नवंबर 2011 के समझौतों में शुल्क निर्धारण के आधार पर अपीलार्थी पर पानी के बिल उठाए गए थे।

5. 18 जुलाई 2014 को, अपीलार्थी को सहायक कार्यकारी अभियंता से एक मांग सूचना प्राप्त हुई थी जिसके द्वारा पानी की नई दरों को लागू करने की मांग की गई थी और अपीलार्थी को विभिन्न शर्तों का भुगतान करने के लिए कहा गया था।

1 “बोर्ड”।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

20 जुलाई 2011 से 30 जून 2014 तक प्रभावी अधिनियम के साथ राशि। संचार के प्रासंगिक भाग को नीचे निकाला गया है:

“...बोर्ड बिनागा, कारवार में आपके उद्योग और आवासों को थोक में पानी की आपूर्ति कर रहा है। 18.40/KL और रु। 9.20/KL क्रमशः संदर्भ (1) के तहत अनुमोदित दर के अनुसार। रेफरी (2) के तहत सरकारी आदेश में पानी की दरों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

स्लैब	औद्योगिक दरें	गैर-घरेलू दरें
0-8 के एल	@ रु. 28.00-KL	@ रु. 14.00/KL
8-15 के एल	@ रु. 36.00 KL	@ रु. 18.00/KL
15 - 25 के एल	@ रु. 44.00 KL	@ रु. 22.00 KL
25 के एल से ऊपर	@ रु. 52.00/KL	@ रु. 26.00/KL

इस उप-मंडल के लेखापरीक्षा के दौरान, बोर्ड के आवासीय लेखापरीक्षा कार्यालय ने पानी की दर में संशोधन न करने के लिए एक लेखापरीक्षा पैरा उठाया है और नए जल दरों को लागू करने और जी. ओ. की तारीख से सभी उपभोक्ताओं से अलग-अलग राशि एकत्र करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, आपकी औद्योगिक और गैर-घरेलू आपूर्ति के लिए बकाया राशि सहित कुल 2 अलग-अलग बिलों को भुगतान करने के लिए जमा किया जाता है।” 6. अपीलार्थी ने 5 अगस्त 2014 को मांग का जवाब दिया और कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और जल निकासी बोर्ड के साथ बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की। 22 सितंबर 2014 को, एक और नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि बोर्ड नो-प्रोफी टी-नो-लॉस के आधार पर काम करता है, और एचईएससीओएम 2 को बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। नोटिस में कहा गया है कि एच. ई. एस. सी. ओ. एम. के बकाया का भुगतान करने में बोर्ड की विफलता से बिजली और पानी की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा। बोर्ड को हुए नुकसान और सरकारी आदेशों के तहत पानी के बिलों में संशोधन न करने के खिलाफ लेखा परीक्षा अधिकारियों की आपत्तियों का हवाला देते हुए, नोटिस में संशोधित दरों के अनुसार बकाया भुगतान का अनुरोध किया गया है।

7. 15 अक्टूबर 2014 को, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से बकाया की मांग करने वाले नोटिस को वापस लेने का अनुरोध किया। उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में, अपीलार्थी ने 18 जुलाई 2014 और 22 सितंबर 2014 के नोटिसों को चुनौती दी।

2 हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड

सोलारिस चेम टेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम असिस्टेंट

467

एक्जीक्यूटिव इंजीनियर कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और ड्राइंग बोर्ड 468

8. अपीलार्थी ने तर्क दिया कि i) विवादित नोटिस पक्षों के बीच समझौतों के खंड 4 के विपरीत थे; ii) 20 जुलाई 2011 की अधिसूचना, समझौतों के समय से पहले होने के कारण, लागू नहीं थी और जल शुल्क बढ़ाने के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था; और iii) शुल्कों में वृद्धि

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ थी क्योंकि प्रतिवादी ने अपीलार्थी को सुने बिना स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्य किया था।⁹ एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि समझौतों के खंड 11 में यह निर्धारित किया गया था कि पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का समाधान पहले आपसी चर्चा द्वारा और प्रक्रिया की विफलता पर, मामले को मुख्य अभियंता, दूसरे प्रतिवादी को भेजकर किया जाएगा, जिसका निर्णय अनिवार्य और बाध्यकारी होगा। एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि समझौतों के खंड 4 के संदर्भ में, बोर्ड दरों को बढ़ाने का हकदार था। हालांकि, खंड 11 में प्रदान किए गए विवाद समाधान तंत्र को देखते हुए, एकल न्यायाधीश ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को समझौते के संदर्भ में संविदात्मक उपचार के लिए भेज दिया।

10. डिवीजन बेंच ने एक रिट अपील में एकल न्यायाधीश के फैसले को स्वीकार कर लिया है। खंड पीठ ने समझौते के खंड 11 की भाषा ("सभी विवाद और मतभेद जो उत्पन्न हो सकते हैं") की ओर रुख किया और अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि विवादित नोटिसों के माध्यम से की गई "मांग" खंड 11 के तहत "विवादों" के दायरे से बाहर थी। इसलिए, खंड पीठ ने कहा कि विवादित नोटिसों से उत्पन्न विवाद समझौते के दायरे में आता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

11. संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इन कार्यवाहियों में नोटिस जारी होने के बाद, प्रतिवादी पेश हुआ है और उसने एक जवाबी कार्रवाई का नेतृत्व किया है।

12. हमने अपीलार्थी की ओर से पेश वकील श्री दलीप कुमार मल्होत्रा और प्रत्यर्थियों की ओर से पेश वकील सुश्री अमृता शर्मा को सुना है।

13. अपीलार्थी का तर्क है कि डिवीजन बेंच ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए इस मुद्दे का गलत अर्थ निकाला है। यह तर्क दिया जाता है कि चुनौती का प्रमुख आधार कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड अधिनियम के तहत वैधानिक प्रक्रिया का पालन न करना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

विवादित नोटिस। अपीलार्थी के अनुसार, उच्च न्यायालय को बोर्ड के इस अधिकार पर विचार करना चाहिए था कि i) सहमत दरों के अलावा शुल्क में वृद्धि की जाए। (ii) सरकारी अधिसूचना के आधार पर ऐसा करना, जो समझौते से पहले की हो। (iii) समझौतों और कानून का उल्लंघन करते हुए कार्य करना जो इसकी शक्ति का स्रोत है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विवाद व्यक्तिगत रूप से नहीं था और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को वैध रूप से लागू किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि समझौतों के खंड 11 में पक्षों को खारिज करके, न्यायालय ने गलती से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

14. हमारे विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय को पक्षों के बीच समझौतों के खंड 11 के बल पर रिट याचिका और रिट अपील को खारिज करने में न्यायसंगत ठहराया गया था। हमें इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या पक्षों के बीच एक वैध मध्यस्थता समझौता था, जो खंड 11 के तहत मुख्य अभियंता को भेजे जाने को उचित ठहराता है।

15. रिट याचिका को खारिज करते समय, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने समझौतों के खंड 11 पर भरोसा किया। खंड 11 इस प्रकार है:

“क्लॉज:11 विवाद का निपटान

11.1 किसी भी प्रावधान के अर्थ से संबंधित या समझौते के संबंध में पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों या मतभेदों को आपसी चर्चा द्वारा हल किया जाएगा।

11.2 यदि आपसी चर्चा विफल हो जाती है तो समझौते में मेरे प्रावधानों के अर्थ से संबंधित बोर्ड और उपभोक्ता के बीच उत्पन्न हुए ऐसे सभी विवादों को मुख्य अभियंता (उत्तर), धारवाड़ को लिखित रूप में भेजकर हल किया जाएगा, जिसका निर्णय उपभोक्ता और बोर्ड पर अनिवार्य और बाध्यकारी होगा।”

16. खंड 11 का शीर्षक है, "विवादों का निपटान"। खंड 11.1 में कहा गया है कि समझौते में या उसके संबंध में किसी भी प्रावधान के अर्थ से संबंधित पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों या मतभेदों को आपसी चर्चा द्वारा हल किया जाएगा। हालांकि, यदि आपसी चर्चा विफल हो जाती है, तो खंड 11.2 में कहा गया है कि बोर्ड और उपभोक्ता के बीच समझौतों के प्रावधानों के अर्थ से संबंधित ऐसे सभी विवादों का समाधान मुख्य अभियंता को भेजकर किया जाएगा, जिसका निर्णय अनिवार्य और बाध्यकारी होगा।

सोलारिस चेम टेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम असिस्टेंट

469

एक्जीक्यूटिव इंजीनियर कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और ड्राइंग बोर्ड 470

17. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 3 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि खंड 11 एक मध्यस्थता समझौते का गठन नहीं करता है। "मध्यस्थता समझौता" शब्द को धारा 2 (बी) द्वारा धारा 7 में निर्दिष्ट समझौते के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 7 का सार नीचे दिया गया है: “7. मध्यस्थता समझौता।—(1) इस भाग में, "मध्यस्थता समझौते" का अर्थ है पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता को उन सभी या कुछ विवादों को प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता जो उत्पन्न हुए हैं या जो उनके बीच एक अवज्ञाकारी कानूनी संबंध के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वह संविदात्मक हो या नहीं।

(2) एक मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है। (3) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा।

(4) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि यह (ए) पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ में निहित है;

(बी) पत्रों, टेलेक्स, तार या दूरसंचार के अन्य साधनों का आदान-प्रदान जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से संचार शामिल है जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं; या

(ग) दावे और बचाव के बयानों का आदान-प्रदान जिसमें समझौते के अस्तित्व का आरोप एक पक्ष द्वारा लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है।

(5) मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेज़ के लिए एक अनुबंध में संदर्भ एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदि अनुबंध लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है कि उस मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा बनाया जाए।”

18. धारा 7 की उप-धारा (1) इंगित करती है कि एक मध्यस्थता समझौता पक्षों द्वारा मध्यस्थता को प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता है "सभी या कुछ विवाद जो उत्पन्न हुए हैं या जो उनके बीच एक अवज्ञाकारी कानूनी संबंध के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे संविदात्मक हो या नहीं।" यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यह निर्धारित करने में कि क्या कोई मध्यस्थता समझौता है, पक्षों के बीच अनुबंध की शर्तों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। 1996 का अधिनियम ऐसा करता है

3 “1996 का अधिनियम ”/“ अधिनियम ”

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

मध्यस्थता समझौते का एक निश्चित रूप निर्धारित न करें। 'मध्यस्थता' शब्द का उपयोग या अनुपस्थिति निर्णायक नहीं है और मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए पक्षों का इरादा स्पष्ट होना चाहिए।

खंड की शर्तों से। जगदीश चंदर बनाम रमेश चंदर,

न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कारकों का सारांश दिया कि क्या कोई समझौता 1996 के अधिनियम की धारा 7 के अर्थ के भीतर एक मध्यस्थता समझौता है। न्यायालय ने 4 अभिनिर्धारित किया:

“(ii) भले ही "मध्यस्थता" और "मध्यस्थ न्यायाधिकरण (या मध्यस्थ)" शब्दों का उपयोग निपटान की प्रक्रिया के संदर्भ में या निजी न्यायाधिकरण के संदर्भ में नहीं किया जाता है, जिसे विवादों के निपटान से संबंधित खंड में विवादों पर निर्णय लेना है, यह खंड को मध्यस्थता समझौते से अलग नहीं करता है यदि इसमें मध्यस्थता समझौते के गुण या तत्व हैं। वे इस प्रकार हैं: (क) समझौता लिखित रूप में होना चाहिए। (ख) पक्षकारों को अपने बीच किसी भी विवाद (वर्तमान या

भविष्य) को निजी न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए संदर्भित करने के लिए सहमत होना चाहिए था।
(ग) निजी न्यायाधिकरण को करना चाहिए

पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर देते हुए, विवादों पर निष्पक्ष तरीके से निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए।

उसके सामने मामला।(घ) पक्षकारों को इस बात पर सहमत होना चाहिए था कि विवादों के संबंध में निजी न्यायाधिकरण का निर्णय उन पर बाध्यकारी होगा।” (जोर दिया गया)।

19. निम्नलिखित शर्तों को एक वैध मध्यस्थता समझौते द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए:

(i) समझौता लिखित में होना चाहिए, जैसा कि धारा 7 की उप-धारा (3) द्वारा निर्धारित किया गया है;

((ख) पक्षकारों को अपने बीच किसी भी वर्तमान या भविष्य के विवाद को मध्यस्थता न्यायाधिकरण को भेजने के लिए सहमत होना चाहिए था।

((ग) मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पक्षकारों को उचित अवसर देते हुए निष्पक्ष तरीके से विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए; और

4 (2007) 5 एससीसी 719,724.

सोलारिस चेम टेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम असिस्टेंट

471

एकजीक्यूटिव इंजीनियर कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और ड्राइंग बोर्ड 472

((iv) पक्षकारों को इस बात पर सहमत होना चाहिए था कि न्यायाधिकरण का निर्णय उनके बीच बाध्यकारी होगा।

20. वर्तमान मामले में, समझौते का खंड 11.2 मुख्य अभियंता को एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के रूप में गठित नहीं करता है। एक समान खंड

इस न्यायालय द्वारा जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बनाम अजय सेल्स एंड सप्लायर्स में विचार किया गया था।⁵ एक वितरणकर्ता

पक्षकारों के बीच समझौते में खंड 13 में एक मध्यस्थता खंड निहित था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि समझौते से या किसी भी तरह से संबंधित या उससे संबंधित उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, जो भी एकमात्र मध्यस्थ, अध्यक्ष, जयपुर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड को भेजे जाएंगे और उनका निर्णय पक्षकारों पर अनिवार्य और बाध्यकारी होगा। तदनुसार, मामले में प्रतिवादी ने अध्यक्ष से संपर्क किया और जब विवाद अध्यक्ष के समक्ष लंबित था, तो प्रतिवादी ने एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन किया और उच्च न्यायालय द्वारा एक मध्यस्थ की नियुक्ति की गई। इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी ने इस न्यायालय का रुख किया। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 12 (5), जिसे वर्ष 2015 में एक संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था, इंगित करती है कि

इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद, कुछ व्यक्ति जिनके पक्षकारों के साथ संबंध अधिनियम की सातवीं अनुसूची के तहत आते हैं, वे मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य हैं। मुद्दा यह था कि क्या यह अयोग्यता 23 अक्टूबर 2015 को लागू हुए संशोधन से पहले निष्पादित मध्यस्थता समझौतों पर लागू होती है। अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने याचिका में प्रश्न का उत्तर दिया। टिप्पणियों को दोहराते हुए

वायस्टाल्पाइन शियेनन जी. एम. बी. एच. बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड **6**, न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 12 (5) का उद्देश्य और उद्देश्य "मध्यस्थों की तटस्थता" सुनिश्चित करना है। गैर-अस्थाई खंड संशोधन-पूर्व समझौतों पर इस प्रावधान के अनुप्रयोग को बहुत स्पष्ट करता है।

21. न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 12 (5) का प्रभाव यह है कि पक्ष इस तरह के समझौते के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति पर जोर नहीं दे सकता है। अधिनियम की सातवीं अनुसूची के साथ धारा 12 (5) को पढ़कर यह अभिनिर्धारित किया गया कि उस मामले में सभापति को अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

5 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 730, पैरा 10। 6 (2017) 4 एससीसी 665।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

और यह कि उच्च न्यायालय को अध्यक्ष के अलावा एक अन्य मध्यस्थ की नियुक्ति में न्यायसंगत ठहराया गया था।

“अधिनियम की सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (5) के तहत अयोग्यता/अपात्रता को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और उस उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए जिसके लिए अधिनियम की सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (5) को अंतःस्थापित किया गया था। सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (5) को मध्यस्थों की 'निष्पक्षता और स्वतंत्रता' को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया है। इसे 'मध्यस्थों की तटस्थता' के उद्देश्य से जोड़ा गया है। मध्यस्थों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही की पहचान है जैसा कि वोएस्टाल्पाइन शियेनन (सुप्रा) के मामले में देखा गया है। पक्षपात के खिलाफ नियम प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों में से एक है जो सभी न्यायिक कार्यवाहियों और अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है और यही कारण है कि संविदात्मक रूप से सहमत होने के बावजूद, अधिनियम की सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (5) में उल्लिखित व्यक्ति स्वयं को मध्यस्थता करने के लिए अयोग्य बना देंगे।” 7

22. वर्तमान मामले में, समझौतों में यह नहीं कहा गया है कि मुख्य अभियंता पक्षों के बीच विवादों पर निर्णय लेगा और न ही इस आशय का कोई प्रावधान है कि मुख्य अभियंता साक्ष्य देने या पक्षों को उनके समक्ष अपने-अपने मामले पेश करने का अवसर देने के बाद विवाद का समाधान करेगा। मुख्य

अभियंता वाले मंच में मध्यस्थता मंच का अभाव है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य अभियंता बोर्ड का एक कर्मचारी होता है। मैं।

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय का दृष्टिकोण, जिसे एलोरा पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम एलोरा पेपर मिल्स लिमिटेड में बरकरार रखा गया है।

एम. पी. की स्थिति, 8 मध्यस्थता कार्यवाही को पूर्वाग्रह और उचित प्रक्रिया के खिलाफ नियम के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। अधिनियम की सातवीं अनुसूची का खंड (1) पक्षकारों में से किसी एक के कर्मचारी को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य ठहराता है। यह निषेध इसके विपरीत एक समझौते के बावजूद लागू होता है। वैध मध्यस्थता की आवश्यकताओं के साथ-साथ पढ़ें।

7 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 730, पैरा 17. 8 (2022) 3 एससीसी 1.

सोलारिस चेम टेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम असिस्टेंट

473

एक्जीक्यूटिव इंजीनियर कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और ड्राइंग बोर्ड 474

जगदीश चंदर (ऊपर), धारा 12 (5) में निर्धारित समझौता

अधिनियम और सातवीं अनुसूची इंगित करेगी कि ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से और पक्षपात के बिना पक्षों के बीच विवाद को हल करने के लिए उचित नहीं माना जा सकता है।

23. यद्यपि एकल न्यायाधीश का विचार था कि समझौते के खंड 4 ने बोर्ड को अपनी दरों को संशोधित करने का अधिकार दिया है, फिर भी, शक्ति और इसके प्रयोग के तरीके के बारे में आगे कोई विचार किए बिना, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को मुख्य अभियंता के समक्ष खंड 11 के तहत उपचार के लिए हटा दिया।

24. एक बार जब हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि खंड 11 के प्रावधान एक मध्यस्थता समझौते का गठन नहीं करते हैं, तो परिणाम यह होता है कि उच्च न्यायालय को खंड 11 के बल पर पक्षों को मुख्य अभियंता के पास नहीं भेजना चाहिए था। यह उचित होता यदि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कार्यवाही में अपीलार्थी द्वारा संबोधित चुनौती को अंतिम रूप से निर्धारित करता। यद्यपि एकल न्यायाधीश ने खंड 4 का समर्थन किया है, स्पष्ट रूप से उस संबंध में कोई अंतिम निर्धारण नहीं है।

25. डिवीजन बेंच के फैसले ने इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए विशेष रूप से खंड 11 के प्रावधानों पर भरोसा किया है कि पक्षों के बीच विवाद खंड के दायरे में आता है। हालाँकि, मामले का मूल पहलू यह है कि खंड 11 में निहित विवादों के निपटारे का प्रावधान मुख्य अभियंता को एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के रूप में गठित नहीं करता है क्योंकि उसे एक निष्पक्ष अधिकारी के रूप में नहीं माना जा सकता है और न ही खंड 11 के प्रावधानों में एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के उपबंध शामिल हैं।

26. उपरोक्त कारणों से, हम अपील की अनुमति देते हैं और 27 फरवरी 2018 के एकल न्यायाधीश के फैसले और 18 जून 2018 के डिवीजन बेंच के फैसले दोनों को दरकिनार कर देते हैं। रिट याचिका, जो कि रिट याचिका संख्या 111298/2014 (जी. एम.-आर. ई. एस.) है, नए सिरे से निर्णय लेने के लिए धारवाड़ पीठ में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को बहाल कर दी जाएगी।

27. हम स्पष्ट करते हैं कि हमने उस मामले के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है जिसे रिट याचिका में अपीलार्थी द्वारा स्थापित करने की मांग की गई है या बचाव पक्ष पर जिसका प्रतिवादियों की ओर से आग्रह किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

28. अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि इस बीच, अपीलकर्ता, जिसे आदित्य बिड़ला समूह ने अपने हाथ में ले लिया है, ने संशोधित जल दरों का भुगतान करना जारी रखा है और उपचार का लाभ उठाने के अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। अपीलार्थी समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों का भुगतान करना जारी रखेगा, जो उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में पारित किए जाने वाले ऐसे आदेशों के अधीन होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायालय को बहाल किया जाता है।

29. तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

30. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील का निपटारा किया गया।

निधि जैन।